Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee may be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Members will be informed accordingly.

13.14 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 28th July, 1980, will consist of:—

(a) Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper.

(2) Discussion on the Resolution seeking approval for increasing the limit of loan to be raised by the Assam States Electricity Board.

(3) Consideration and passing of the Mica Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 1980.

(4) Discussion on the Resolution seeking approval of the draft Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1980.

(5) Consideration of the motion for modification of the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1980, given notice of by Shri R. K. Mhalgi.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Minister has just announced the business for the next week. I urge upon the Government to make a statement on a very important, and delicate and crucial issue.

The Israeli Parliament is rushing through a Bill in order to declare Jerusalem, including the annexed Arab sector, as its capital. The Fiast Reading is already over and the second and the third Readings of that Bill are expected to be completed by the 30th of this month. All this is being done at a time when the Extra-ordinary Session of the United Nations is debating the entire question about Palestine.

Sir this attitude of Israel is in flagrant violation of world opinion and the United Nations Resolution. They have repeatedly declared, and the Prime Minister of Israel got up from his sick bed in order to attend the Parliament to vote on this Bill declaring that Jerusalem will be an indivisible capital of Israel for all generations to come and it will be an eternal capital. All this is happening, as I said, in flagrant violation of the world opinion, in flagrant violation of the United Nations Resolution. I, therefore, urge upon the Government to come forward with a statement expressing anguish and indignation and also, in order to retaliate, in consonance with the world opinion, announcing the closure of the Israeli Consulate at Bombay and invoking more political and economic sanctions by India against Israel.

The second item that I would like the hon. Minister to consider is that the hon. Minister for Irrigation made a statement in this House on 15th July 1980 regarding the outcome of the 19th Meeting of the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission held at Dacca from 9th to 11th July, 1980. This statement must be considered in this House because we must all try to see that the impasse that has unfortunately come up is solved and we move ahead with the purpose for which this Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission is there. I have already given a motion under Rule 189. It is motion No. 139, and I urge upon the Government that for an early solution for mutual benefit, this particular motion be considered at the earliest by the House.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I would suggest that

[Prof. Madhu Dandvate]

in the Government Business for the coming week some of the items that I am suggesting may be included either by way of a statement by the Minister or by way of a number of notices given by me. I gave a very wide choice to the Speaker right from the adjournment motions up to matters under Rule 377. Whatever is possible may be admitted.

The first issue that I would like to be included is that there has been a news item in the newspapers that the US President had already ordered a new naval force of 1800 marines and 5 warships into the Indian Ocean That makes the Indian Ocean not a zone of peace, but a zone of power conflict between the USA and the USSR. Therefore, either a statement should be made on this by the External Affairs Minister or some discussion should be arranged.

News about the prospect of resumption of talks between the Government and the leaders of the All Assam Students Union and the Gana Sangram Parishad and the reported mediation efforts by the Manipur Chief Minister to facilitate such talks to settle the foreigners issue amicably has already appeared in the press. If the problem can be settled amicably, it is a very welcome development from the point of view of integration of the country and getting over the present impasse. We would like to know from the hon. Home Minister what the prospects of an amicable settlement are.

Lastly there is a reported move by the Reserve Bank to resist the decisions of the Tamil Nadu and the Maharashtra Governments to write off loans given to small farmers. I think this is a very serious matter and on that also the oncerned Minister should come out with a categorical statement.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि संसद्-कार्य मंत्री महोदय ने आगामी सप्ताह के लिए कार्य का जो विवरण पेश किया है, उसमें सरकारी काम के अलावा और किसी काम के लिए समय की व्यवस्था नहीं की गई है। यह तय हुआ था कि वित्त विधेयक पर विचार की समाप्ति के बाद हम उस हवाई दुर्घटना पर चर्चा करेंगे, जिसमें श्री संजय गांधी की मृत्यु हुई थी। मैं समझता हूं कि वह विषय हमारे मानस को मथ रहा है। देश में भी उसके बारे में सारे तथ्यों को जानने की उत्सुकता है। उस पर जितनी जल्दी बहस की जाये, उतना, अच्छा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जो उत्तर मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक उनका उत्तर नहीं मिल रहा है।

जो हवाई जहाज कस्टम्ज द्वारा जब्त कर लिया गया था, वह कैसे छोड़ दिया गया? उसका मालिक कौन था? और दिल्ली फ्लाइंग क्लब किस तरह से चल रहा है? क्या यह सच है कि दिल्ली फ्लाइंग क्लब का हवाई जहाज उड़ाने के लिए फ्युअल दिया जाता है, और उसके लिए हर महीने फ्युअल का कोटा बंधा हुआ है, और जिस दिन पैट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, उससे एक दिन पहले दिल्ली फ्लाइन्ग क्लब की ओर से 35,000 लिटर पैट्रोल निकाल लिया गया? मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों में कहा तक सच्चाई है? ये बातें तभी उठाई जा सकती हैं, जब उस दुर्घटना पर इस सदन में गहराई से चर्चा हो। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उसके लिए जल्दी से जल्दी समय तय करें।

आपातस्थिति की घोषणा केन्द्रीय सरकार ने की थी। उसके अन्तर्गत अनेक राज्यों में ज्यादतियां हुई। राज्य सरकारों ने उन ज्यादतियों की जांच के लिए कमीशन बनाये। पंजाब में इसी तरह का गुरदेव सिह कमीशन कायम हुआ था? पंजाब में चुनाव के बाद नई सरकार आ गई, लेकिन उसने उस कमीशन को भंग नहीं किया।

इसका अर्थ यह है कि श्री दरबारा सिंह की सरकार यह समझती थी कि आपातस्थिति के दौरान ज्यादतियां हुई हैं और उनकी जो जांच हो रही हैं, वह ठीक है। इसीलिए विधान सभा की बैठक जिस दिन स्थगित हुई, उसी दिन गुरदेव कमीशन की रिपोर्ट को विधान सभा के सभा-पटल पर रख दिया गया। मैं उस रिपोर्ट के तीन भागों की प्रतियां प्राप्त करने में सफल हो गया हूं। कहा जा सकता है कि पंजाब में इमर्जेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई, उनसे इस सदन का क्या सम्बन्ध है। मेरा निवेदन है कि इस समय जो हमारे गृह मंत्री हैं...

MR DEPUTY-SPEAKER: That is the proprty of the Punjab Assembly. How did you get it?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It is public property.

उस समय के पंजाब के मुख्य मंत्री इस समय हमारे गृह मंत्री हैं और कमीशन ने उनके आचरण पर भी कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री ऐसे होने चाहिए, जिन पर कोई आक्षेप न हों। वह प्रदेश से देश में आ गये हैं। लेकिन व्यक्ति के नाते ज्ञानी जैल सिंह वही बने हुए हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are asking for a discussion on this. By this you are having a discussion now!

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो चाहता हूं, वह हमारे गृह मंत्री हैं, सदन के सदस्य हैं, अगर उनके आचरण पर कोई टिप्पणी हुई है और टिप्पणी कमीशन के द्वारा हुई है तो यह गंभीर मामला है और इस को दबाया नहीं जा सकता। इस मामले का सफाई के साथ गृह मंत्री महोदय को सामना करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सदन को इस बारे में अपनी राय प्रकट करने का मौका मिले।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Harikesh Bahadur. Because you have not mentioned any particular item, I will give you only three minutes. Please be brief.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के तमाम सूबों में खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, मणिपुर, केरल, कर्नाटक गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि अनेक राज्यों में बाढ़ की विभीषिका छायी हुई है। हजारों घर गिर चुके हैं। कई सौ जानें गई हैं। कई अरब रुपए की सम्पत्ति की हानि हुई है। केवल उत्तर प्रदेश में 23 जिलों के लगभग 4 हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक है। मरने वालों की संख्या 250 से अधिक है। सम्पत्ति की हानि 250 करोड़ से अधिक हुई है। तमाम जगहों में सेना को बुलाया गया है मदद के लिए। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी आदि तमाम जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हम लोगों ने 193 नियम के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया है। उस पर बहस कराने के लिए हम लोगों ने स्पीकर महोदय से भी प्रार्थना की थी। मैं चाहता हूं कि इस पर बहस जरूर करायी जाये ताकि बाढ़ की इस विभीषिका से प्रभावित बहुत से सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर कह सकें जिस से सरकार उस पर कार्यवाही कर सके।

दूसरी बात—यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए। यह बहुत दिनों से नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। उस पर बहस होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर भी यहां चर्चा नहीं हुई है। इसलिए यू जी सी की रिपोर्ट पर अवश्य बहस होनी चाहिए।

अन्तिम बात—गुरदेव सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर अवश्य बहस होनी चाहिए इस सदन के अंदर क्योंकि वह (श्री जैल सिंह)

भारत के गृह मंत्री हैं और सदन के माननीय सदस्य हैं। उनके ऊपर उसमें आक्षेप किए गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस पर बहस हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mhalgi. You should also take only three minutes.

SHRI R. K. MHALGI: (Thane): I would like to submit only one point, which will require not more than 2½ minutes. I want the Government to make a statement next week on the following matter of urgent importance. This item should, therefore. be included in the next week's business.

The Government of India have in the last three months secured record credits from World Bank, International Development Association, etc. These credits amount to $1600 million in fiscal year 1980 as compared to $ 1492 million in 1979 and $ 1281 million in 1978. I find it difficult to rejoice in borrowing more and more money. Indeed I do not see any reason whv we should go in so much for these loans, whether soft or not soft. We have foreign exchange reserves, enough of our own, not to be seeking loans abroad. And it does not add to the self-respect of any nation to be going round with a begging bowl for foreign credits.

World financial institutions have a vested interest in offering us credits aid influencing our policies. They make us feel poor, helpless and dependent. We should, therefore, not only seek loans but also we should refuse them even if offered.

Much of the economic inefficiency of our public sector projects is rooted in the psychology of "laid". We seem to behave as though "aid" were a gift when it is only a loan, carrying a certain rate of interest. This Psychology has caused us to borrow lavishly, invest unwisely and lose heavily.

We know that we might be paying a lower rate of interest on foreign loans that we can earn on our own lendings. But simple self-respect and the powerful psychology of Independence-demand that we do not go in for so much foreign loan as in the last few months. I, therefore, urge upon the Government to make a statement on this important issue next week.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mhalgi. you are making a statement to get a settlement from the Minister.

SHRI R. K. MHALGI: You have given me three minutes to put my submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the item to be included?

SHRI R. K. MHALGI: I have already stated that this is my point, on which the Minister concerned should make a statement next week.

श्री रामावतरा शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहला सवाल जो अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाए वह है दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश जिसको लेकर बहुत ही गोल-माल हो रहा है और दिल्ली के अखबारों में रोज कोई न कोई कहानी निकल रही है। इसके कारण लोग परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, छात्र परेशान हैं और उनका एडमीशन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने शिक्षा विभाग की मांगों पर बहस भी नहीं की इसलिए मैं चाहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में जो एडमीशन का सवाल एक विकराल रूप में सामने उपस्थित है उस विषय पर भी अगले सप्ताह बहस करने का समय निर्धारित किया जाए।

दूसरी बात ला एंड आर्डर से सम्बंधित है। आज के ही अखबारों में निकला है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक परिवार के सात व्यक्तियों को गला घोंट कर मार दिया गया। स्वयं सरकार भी कहती है कि हत्याओं को रोका नहीं जा सका है, रोज हत्यायें बढ़ रही हैं। दिल्ली में और देश के विभिन्न हिस्सों में सबसे अफसोस और चिंता की बात यह है कि ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्यायें हो रही हैं और बड़े पैमाने पर हो रही हैं। ला एंड आर्डर में वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि राजनीतिक हत्यायें भी हो रही है और आम लोगों की हत्यायें भी हो रही है इसलिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अन्त में, यहां पर जो बाढ़ के सम्बन्ध में बहस की मांग की गई है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक 319 आदमी अब तक बाढ़ों में मर चुके हैं। इसलिए यह भी बहुत आवश्यक सवाल है। जब हमने कृषि विभाग की मांगों पर बहस की थी उस समय बाढ़ का रूप आज जैसा नहीं था इसलिए उस समय हम बहस नहीं कर सके। इसलिए आवश्यक है कि इस सवाल पर भी इस सदन में विचार किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Narayan Choubey.

Your points are crystal-clear. Therefore, you can even just read out. One is discussion on bonus; everybody knows about it.

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): Yes. Sir. The bonus issue must be settled before the festival season comes in. The Durga Pooja and Ganesh Pooja are coming. That is the first item.

The second is about jute. We will be having very good jute this year, but jute prices have not yet been fixed. We want that jute prices should be fixed and that the STC must be forced to buy jute. This should be on the Agenda.

Thirdly, as other friends have also stated the Gurudev Singh Commission indicating the Hon. Home Minister should be made an issue. We want that this should be discussed.

Fourthly, yesterday's papers have stated that in West Bengal for the Santaldih plant we are not getting coal. Instead of coal, ash is supplied through wagons. I want this issue also to be discussed. We want to know what is actually being supplied We are short of power and if the Santaldih plant fails due to non-supply of coal we will be hard put.

Today's paper has got one point which I think should be discussed. The Central Government officials who stood witness before the Shah Commission are still being harassed. They are being transferred; they are not being allowed to joint; duty. I think this should be on the agenda for discussion.

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले सप्ताह में मैं दो आइटम रखने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूं। पहला महिलाओं के संबंध में ला कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं, इसके बारे में सदन मे चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। हमारे देश में ग़रीब तबके की महिलायें, हरिजन-आदिवासी और ग़रीब किसान मजदूरों की महिलायें असुरक्षित हैं। इनके लिए कानून में तबदीली करना बहुत आवश्यक है। महिला संगठन ने जो लां-कमीशन को सुझाव दिए थे, उनमें से बहुत से उन्होंने मन्जूर कर लिए हैं। उन्होंने इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एवीडेंस एक्ट में तबदीली करने के लिए जो सुझाव रखें हैं, उन पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिए तथा कानूनी रूप में उसको हमारे सामने लाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गौड़ जैसे लोग, जो बागपत में आज खुले फिर रहे हैं, उनको छुटकारा नहीं मिलेगा।

दूसरा सुझाव यह है कि बहुत दिनों से अखबारों में खबर आ रही है कि इंडियन रेडक्रास सोसाइटी में बहुत गड़बड़ चल रही है, लाखों रुपयों का सामान सड़ रहा है। जिसमें मिल्क पाउडर, चीनी और बेबीफूड आदि चीजें हैं। 1972 में जो बंगलादेश के लिए सामान आया था, उसमें बहुत सी चीजें ब्लैक मार्केट में, बाजारों में, बेची गई है। ऐसी शिकायतों पर श्री पिमपुटकर ने, जो विजीलेंस कमीशनर है, रिपोर्ट भी दी है। मुझे यह भी निवेदन करना है कि उन्होंने जिन लोगों पर ऐसे कामों की जिम्मेदारी डाली थी, अब जो कमेटी रि-कांस्टीचूट हुई है, उस कमेटी में भी उन्हीं लोगों को लिया गया है, जिससे इंडियन रेड क्रास का काम काफी ठप्प हो रहा है। वर्ल्ड-बैंक में भी गड़बड़ चल रही है और बहुत सा सामान सड़ रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jyotirmoy Bosu. He has not mentioned any item. He may make a speech for three minutes.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Is it important that items are indicated, Sir? What is the number of the Direction under which it is compulsory?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have only said there is no item in your name.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Right, Sir.

Now, specific charges have been levelled and original and authenticated documents have been produced. I take the responsibility of proving that in the distribution of coal to 133 parties, mostly in Malda District which falls within the constituency of Mr. A. B. A. Ghani Khan Chaudhuri, permits were given illegally, with *mala-fide* intentions. Two Motions are pending before the House. One says, under Rule 184, that for this misconduct, the Minister should be drubbed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: These Motions are under consideration—very active consideration.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I wanted time... (*Interruption*).**

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Sir, this should be expunged.

(*Interruptions*)**

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Why should it be expunged? Is there anything unparliamentary?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: There are two motions: One about... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: If he has said something which is not parliamentary I will go through the proceedings and expunge it. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, you are a veteran Parliamentarian: why all this? It does not look nice—not visibly like this. You are a veteran Parliamentarian:**

You can have consultation...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now come to the subject proper: you might forget.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: My submission is that the two montions should be discussed, keeping in mind what late Pt. Jawaharlal Nehru had done in the case of Mudgal. For conduct unbecoming of a Member, the man was forced to resign. Here, if the Prime Minister does not want to shield this person,**—I can sign on my own responsibility—because the West Bengal Enforcement Police have found out that in many cases the parties did not exist at all, it has

**Expunged as ordered by the Chair.

been given to ghosts and it has gone into the black-market and crossed the river to Bangladesh, therefore, the Motions should be taken up next week.**

SHRI CHITTA BASU (Barasat): I have given a motion regarding the procurement policy, for raw jute, of the Government. The importance of the subject lies in the fact that it appears the Government is going to revise the entire procurement policy for raw jute. You know and the Government knows that when the Jute Corporation of India was established the object for which it was established was declared to be to progressively move towards monopoly procurement of raw jute. Now the Government, it appears, has revised that policy of monopoly procurement, resulting in the reduction of procurement by the JCI with every passing year. The price for jute which is remunerative is not being made available to the jute growers. This year it has been fixed at Rs. 160/- per quintal which is not only unremunerative but also much below the cost of production. I think this is such an important subject that it affects the interests of millions of jute growers spread over six States of our country, particularly the eastern region. I want the Government—and you should also try to help me—to find the time to discuss this subject on which I have given a motion.

My second point is the question of dearness allowance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has been already announced.

SHRI CHITTA BASU: I find a notice that the Hon. Minister is going to make a statement. I do not know what is in that statement, but the fact is that the wholesale price index has risen by 26 points since February this year, making two additional dearness allowance instalments payable. I do not know what is the instalment announced—one or two. My point is that already two instalments have become due and the Government should come out with a statement allowing two instalments of D.A. for Central Government employees. In case he is going to make a statement, I would ask the hon. Minister of Parliamentary Affairs to allow a discussion on that statement, on which we can discuss this point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the statement is to your satisfaction...

SHRI CHITTA BASU: Then I do not require it. But my point is this. I do not know what is in the statement...

MR. DEPUTY-SPEAKER: I also do not know.

SHRI CHITTA BASU: But the price rise has been such that two instalments have already become payable. He should bear this in mind while making the statement.

My third point is this. Much has been said in this House about electoral reforms. An assurance has been given by the Government side on many occasions. I think, Government should include in its list of business some statement or some policy statement, whatever it may be, in the matter of electoral reforms.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): I am extremely grateful to the hon. Members for the valuable suggestions they have made. I can only say that I will look into those suggestions, and those suggestions which are necessary to be brought to the notice of the Business Advisory Committee. I will bring those to their notice. Some of the Members have demanded some statements from the concerned Ministers. I will write to them and if they think proper, they will make the statements.

**Expunged as ordered by the Chair.